बीएसएनएलईयू, एआइबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीएब्ल्यूएफ की समन्वय समिति

05.04.2023 को नई दिल्ली में मजदूर किसान रैली – क्यों?

बीएसएनएल कर्मचारियों को वेज रिवीजन से वंचित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल के कर्मचारी वेज रिवीजन के हकदार नहीं हैं, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीएसएनएल के घाटे का जिम्मेदार कौन है? निस्संदेह, यह सरकार है। बीएसएनएल विरोधी और सरकार की निजी समर्थक नीतियों ने बीएसएनएल को वित्तीय संकट में धकेल दिया है। ताजा उदाहरण यह है कि तमाम निजी कंपनियां अपनी 5जी सेवा शुरू कर रही हैं। वहीं, बीएसएनएल ने अभी अपनी 4जी सेवा भी शुरू नहीं की है। बीएसएनएल की 4जी सेवा इसके मौजूदा 49,300 4जी संगत बीटीएस के उन्नयन के माध्यम से कम से कम 2 साल पहले शुरू की जा सकती थी। लेकिन, सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

इसके बाद जब बीएसएनएल ने 4जी उपकरण खरीदने के लिए टेंडर निकाला तो सरकार ने जबरन उस टेंडर को रद्द कर दिया। Jio, Airtel और Vodafone Idea विदेशी कंपनियों से 5G उपकरण खरीद रहे हैं। लेकिन, सरकार ने बीएसएनएल को नोकिया, एरिक्सन, आदि जैसी विदेशी कंपनियों से अपने 4जी उपकरण खरीदने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। इस प्रकार, सरकार बीएसएनएल को कमजोर करने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन, इसका दोष कर्मचारियों पर मढ़ रहे हैं। यह कैसा न्याय है?

4जी सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण हर महीने लाखों ग्राहक बीएसएनएल छोड़ने लगे हैं। अकेले 2022 में 77 लाख ग्राहक बीएसएनएल छोड़ चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप, बीएसएनएल का पुनरुद्धार एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न बन गया है। सरकार का पूरा विचार बीएसएनएल को एक बीमार कंपनी में बदलना और अडानी जैसे कॉरपोरेट्स को सौंपना है। यह उसी तरह है जैसे एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया गया था।

सरकार ने बीएसएनएल कर्मचारियों को वेज रिवीजन से इनकार करते हुए कहा है कि बीएसएनएल घाटे में चल रही है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन पुनरीक्षण से सरकार वंचित कर रही है। सरकार का कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पुनरीक्षण तभी मिलेगा जब कार्यरत कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण मिलेगा। परोक्ष रूप से सरकार बीएसएनएल के घाटे में रहने के लिए पेंशनभोगियों को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। यह बहुत बड़ा अन्याय है।

प्रबंधन ने वीआरएस के तहत 80,000 कर्मचारियों की छटनी की। इसके साथ ही प्रबंधन ने 20 साल से काम कर रहे हजारों ठेका मजदूरों की बेरहमी से छटनी कर दी। नतीजा यह हुआ कि 7 संविदा कर्मियों ने आत्महत्या कर ली। पुनर्गठन के नाम पर प्रबंधन ने हजारों जेटीओ, जेएओ, सीनियर टीओए, जेई, टीटी और एटीटी पदों को खत्म कर दिया। इसके परिणामस्वरूप नॉन–एक्जीक्यूटिवों की न्यायोचित पदोन्नति से मना किया जा रहा है।

हमें यह समझना चाहिए कि, बीएसएनएल, उसके कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और ठेका श्रमिकों के सामने आने वाली सभी समस्याएं बीएसएनएल विरोधी, सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी, कर्मचारी विरोधी और सरकार द्वारा पालन की जा रही नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

यह हमला केवल बीएसएनएल पर नहीं, बल्कि देश के पूरे सार्वजनिक क्षेत्र पर है। सरकार ने विनिवेश के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एलआईसी के निजीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को खत्म करने और बैंकिंग उद्योग को पूरी तरह से बड़े कॉर्पोरेट्स को सौंपने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

इसके साथ ही सरकार ने कई कदम उठाए हैं और बड़े कॉरपोरेट्स को सुपर प्रॉफिट कमाने में मदद की है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:–

- भारत में अति–अमीर लोगों और बड़े कॉर्पोरेट द्वारा धन कर का भुगतान किया जा रहा था। 2015 में, मोदी सरकार ने इस धन कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
- सरकार बड़े कॉर्पोरेट्स से 30% कॉर्पोरेट टैक्स वसूल करती रही थी। 2019 में सरकार को बड़े कॉरपोरेट्स पर तरस आ गया और इस कॉर्पोरेट टैक्स को 15% तक कम कर दिया।
- 2014–15 के बाद से, सरकार ने ज्यादातर बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा लिए गए 10.72 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण को माफ कर दिया है। (बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा लिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बहुत प्रभावित हुआ है।)
- जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई तो सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटा। पिछले 3 साल में ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल आदि पर टैक्स के रूप में जनता से 8.02 लाख करोड़ रुपये वसूले हैं। बीजेपी नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रसिद्ध टिप्पणी की, 'राम के भारत में पेट्रोल की कीमत 93 रुपये है, जबकि रावण के श्रीलंका में यह केवल 51 रुपये है।'
- भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, खाद्य पदार्थों पर करों को समाप्त कर दिया गया था। पिछले 75 वर्षों के दौरान चावल, गेहूं, दूध, दही, मांस, मछली, पनीर और गुड़ जैसी खाद्य वस्तुओं पर कभी भी कर नहीं लगाया गया। लेकिन, मोदी सरकार ने उपरोक्त खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाया है।
- सबसे क्रूर मूल्य वृद्धि रसोई गैस सिलेंडर पर है। एक साल में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 431.50 रुपए की बढ़ोतरी (76 फीसदी की बढ़ोतरी) की गई है और यह 1,053 रुपए (दिल्ली) में बिक रहा है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर, सरकार उदारतापूर्वक मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्तियों को बड़े कॉर्पोरेट्स को सौंप रही है। इसमें 26,700 किलोमीटर हाईवे (1.6 लाख करोड़ रुपये), 400 रेलवे स्टेशन, 150 ट्रेनें (1.5 लाख करोड़ रुपये), 42,300 सर्किट किलोमीटर बिजली पारेषण लाइनें (0.67 लाख करोड़ रुपये), 5,000 मेगावाट हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन संपत्ति (0.32 लाख करोड़ रुपये), राष्ट्रीय गैस पाइपलाइनों की 8,000 किलोमीटर (0.24 लाख करोड़ रुपये), आईओसी और एचपीसीएल की 4,000 किलोमीटर पाइपलाइन (0.22 लाख करोड़ रुपये), 21 हवाई अड्डे और 31 बंदरगाह (0.3 लाख करोड़ रुपये), 160 कोयला खनन परियोजनाएं (0.3 लाख करोड़ रुपये), 2 खेल स्टेडियम (0.11 लाख करोड़ रुपये) और बीएसएनएल के 14,197 मोबाइल टावर शामिल हैं।

सरकार की उपर्युक्त कारपोरेटपरस्त और मजदूर–विरोधी और जन–विरोधी नीतियों के कारण मेहनतकश जनता तेजी से गरीबी की ओर धकेली जा रही है। वहीं, मोदी सरकार द्वारा दी गई रियायतों की वजह से बड़े–बड़े कॉरपोरेट्स सुपर–रिच मुनाफा कमा रहे हैं। एक आंकड़ा कहता है कि, कोविड महामारी काल में 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया। जबकि इस दौरान अडानी की संपत्ति में हर हफ्ते 6,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। सरकार की नीतियों के कारण ही मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। गौतम अडानी ने उन्हें पछाड़ दिया और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण अमीर अधिक अमीर हो रहे हैं और मेहनतकश कंगाल हो रहे हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है! वहीं, नीचे की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% दौलत है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, भारत में अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई है। मार्च 2020 और नवंबर 2022 के बीच भारत में अरबपतियों ने अपनी संपत्ति में 121% की वृद्धि देखी है, जो प्रति दिन 3,608 करोड़ रुपये की वृद्धि का काम करती है।

मोदी सरकार मजदूर वर्ग के और क्रूर शोषण की जमीन भी तैयार कर रही है। कड़ी मेहनत से जीते गए श्रम अधिकारों को छीना जा रहा है। सभी मौजूदा श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया गया है और 4 नए श्रम संहिता लागू किए गए हैं। व्यावहारिक रूप से मजदूरों के ट्रेड यूनियन शुरू करने के अधिकार और हड़ताल पर जाने के अधिकार पर लेबर कोड के तहत हमले हुए हैं। मजदूर वर्ग को शोषण के खिलाफ एकजुट और शक्तिशाली संघर्ष करने से रोकने के लिए उन्हें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। मेहनतकश जनता के बीच साम्प्रदायिक नफरत का

जहर फैलाया जा रहा है। हाल के वर्षों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर हमले हुए हैं। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार करने के लिए राजद्रोह कानून जैसे क्रूर कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

फिर भी, हमने किसानों के एकजुट संघर्ष को देखा है। सरकार के दमन और खराब मौसम का सामना करते हुए, किसानों ने एक साल तक एकजुट होकर संघर्ष किया। 700 किसानों की जान चली गई। लेकिन, आखिरकार सरकार को संसद द्वारा पारित 3 कारपोरेट समर्थक कृषि अधिनियमों को वापस लेना पड़ा। इसलिए समय की मांग है कि मजदूर, किसान और खेतिहर मजदूर एक साथ आएं और सरकार की जनविरोधी और कारपोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें। इसी भावना के अनुरूप निम्नलिखित मांगों को उठाते हुए दिनांक 05.04.2023 को नई दिल्ली में एक विशाल मजदूर किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है।

1) **सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद करो। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) को रद्द करें।**
2) **चार श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द करो।**
3) **न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह और सभी के लिए पेंशन 10,000 रुपये सुनिश्चित करो। काम का कोई ठेकेदारीकरण नहीं; स्क्रैप अग्निपथ योजना।**
4) **मूल्य वृद्धि को रोकें, खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वापस लें; पेट्रोल/डीजल/मिट्टी/रसोई गैस काफी हद तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करें।**
5) **गारंटीकृत खरीद के साथ सभी कृषि उपज के लिए कानूनी रूप से C2+50% पर MSP सुनिश्चित करें।**
6) **केंद्र सरकार द्वारा सभी गरीब और मध्यम किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए एक बार की ऋण माफी। 60 वर्ष से ऊपर के सभी को पेंशन।**
7) **सभी के लिए नौकरी की सुरक्षा और गारंटी। मनरेगा का विस्तार करें और न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रति दिन के साथ कार्यदिवस बढ़ाकर 200 करें। सभी लंबित वेतनों का भुगतान करें। राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करें।**
8) **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का सार्वभौमीकरण करें और 14 आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करें।**
9) **आयकर दायरे से बाहर सभी परिवारों को भोजन और आय सहायता सुनिश्चित करें।**
10) **वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का कड़ाई से कार्यान्वयन; वन (संरक्षण) अधिनियम और नियमों में संशोधन वापस लें जो केंद्र सरकार को निवासियों को सूचित किए बिना जंगल की कटाई की अनुमति देते हैं।**
11) **उपेक्षित वर्गों का दमन बंद करो और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करो।**
12) **सभी के लिए सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करना; राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को रद्द करें।**
13) **सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना।**
14) **अति धनवानों पर कर लगाओ; कॉर्पोरेट कर बढ़ाओ; वेल्थ टैक्स लागू करों।**

हम बीएसएनएल कर्मचारियों, पेंषनर्स और ठेका मजदूरों से अपील करते हैं कि वे मजदूर किसान रैली को और साथ ही अभियान कार्यक्रमों को भी पूरी तरह सफल बनाएं।

(पी. अभिमन्यु)	(के जी जयराज)	(अनिमेष मित्रा)
जी एस, बीएसएनएलईयू	जी एस, एआइबीडीपीए	एसजी, बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ